गौतम जैन

बनाम

भारत संघ और एक अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 2281/2014)

04 जनवरी, 2017

[ए. के. सिकरी और अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधिपतिगण]

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 धाराये 3, 5 ए- अपीलकर्ता – धारा 3(1) के अंतर्गत निरूद्ध किया गया, निरूद्ध के आधार और कुछ भरोसेमंद दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया गया - अपीलकर्ता ने निरूद्ध आदेश को उच्च न्यायालय में यह कहते हुए चुनौती दी कि उत्तरदाताओं ने निरूद्ध आदेश में एक विशेष आरोप के लिए कुछ दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए - उच्च न्यायालय ने धारा 5 ए में उल्लिखित आधारों के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करते हुए नजरबंदी को बरकरार रखा, यह मानते हुए कि निरूद्ध आदेश विभिन्न आधारों पर आधारित था और इस प्रकार भले ही एक विशेष आधार से संबंधित दस्तावेज अपीलकर्ता को प्रदान नहीं किए गए थे, निरूद्ध आदेश अभी भी शेष आधारों पर कायम रहेगा। अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया : यदि निरूद्ध आदेश एक से अधिक आधारों पर आधारित है, एक-दूसरे से स्वतंत्र है, तो नजरबंदी आदेश कायम रहेगा, भले ही पाए गए आधारों में से एक गैर-मौजूदा या कानूनी रूप से अस्थिर हो – वर्तमान मामले में, निरूद्ध आदेश कई आधारों पर आधारित है, जैसे कि अलग-अलग आधार बनाने वाले विभिन्न कृत्यों का उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर अपीलकर्ता को निरूद्ध किया गया था - इसलिए, एक बार यह पाया जाता है कि निरूद्ध आदेश में कई आधार हैं, भले ही उनमें से एक को खारिज कर दिया गया हो, धारा 5 ए में निहित अलगाव का सिद्धांत आकर्षित होता है - इसलिए, यह तर्क

कि निरूद्ध आदेश केवल एक आधार पर आधारित है और इस प्रकार आधारों की पृथक्करणीयता का सिद्धांत लागू नहीं होता है, खारिज कर दिया जाता है।

शब्द और वाक्यांश: आधार - धारा 5 ए के संदर्भ में, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 का अर्थ।

कोर्ट ने आपराधिक अपील और टैग की गई रिट याचिका को खारिज करते हुये,

अभिनिर्धातिर किया : 1.1 यदि निरूद्ध आदेश एक से अधिक आधारों पर आधारित है, एक-दूसरे से स्वतंत्र है, तो नजरबंदी आदेश तब भी कायम रहेगा, भले ही पाए गए आधारों में से एक गैर-मौजूदा हो या कानूनी तौर पर अस्थिर हो। दूसरी ओर, यदि निरूद्ध आदेश एक समग्र आधार पर स्थापित किया गया है, हालांकि इसमें विभिन्न प्रजातियां या उप-शीर्ष शामिल हैं, तो ऐसे आधार पर गलती पाए जाने पर नजरबंदी आदेश रद्द कर दिया जाएगा। [पैरा 15] [379-बी]

1.2 निरूद्ध आदेश का उचित विश्लेषण करने के लिए, अधिनियम की धारा 5 ए में निहित अभिव्यक्ति 'आधार' के अर्थ को समझा जाना चाहिए। [पैरा 16] [379-बी]

1.3 आधार 'बुनियादी तथ्य' हैं जिन पर निष्कर्ष स्थापित किए जाते हैं और ये सहायक तथ्यों या इन बुनियादी तथ्यों के अतिरिक्त विवरणों से भिन्न होते हैं। प्रत्येक 'बुनियादी तथ्य' एक आधार और उसके समर्थन में विवरण का गठन करेगा या विवरण सहायक तथ्य होंगे या उक्त बुनियादी तथ्यों के अतिरिक्त विवरण होंगे जो 'आधार' का अभिन्न अंग होंगे। अधिनियम की धारा 3 में 'आधार' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अधिनियम में कोई अन्य प्रावधान 'आधार' को परिभाषित नहीं करता है। धारा 3(3) निरूद्ध आदेश के संचार से संबंधित है और कहती है कि 'आधार' जिस पर आदेश दिया गया है, निरूद्ध का आदेश पारित होते ही निरूद्ध में लिए गए व्यक्ति को सूचित किया जाएगा और उस समय सीमा को तय करता है जिसके भीतर ऐसा निरूद्ध आदेश पारित किया जाना

है। यहीं पर अभिव्यक्ति 'आधार' का उपयोग किया जाता है और यही कारण है कि निरूद्ध में लिए गए विस्तृत आधार, जिस पर निरूद्ध का आदेश पारित किया जाता है, प्रदान किया जाता है। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत दी गई विभिन्न परिस्थितियाँ, जिनके आधार पर निरूद्ध आदेश पारित किया जा सकता है, को 'आधार' नहीं माना जा सकता है। विभिन्न उदाहरणों को अलग-अलग आधारों के रूप में माना जाएगा क्योंकि वे बुनियादी तथ्यों का गठन करते हैं जो उन्हें अनिवार्य रूप से 'आधारों' का तथ्यात्मक घटक बनाते हैं और उन उदाहरणों के संबंध में जो अतिरिक्त विवरण दिए गए हैं वे सहायक विवरण हैं। [पैरा 19] [383-बी-एच; 384-ए-बीआई

1.4 निरूद्ध का आदेश कई आधारों पर आधारित है, क्योंकि विभिन्न अलग-अलग कृत्यों का उल्लेख किया गया है, जो अलग-अलग आधार बनाते हैं, जिसके आधार पर निरूद्ध में लेने वाले प्राधिकारी ने यह राय बनाई कि अपीलकर्ता को निरूद्ध में रखना वांछनीय था। अपीलकर्ता का यह तर्क कि निरूद्ध आदेश केवल एक आधार पर आधारित है, खारिज कर दिया गया है। एक बार जब यह पाया जाता है कि निरूद्ध आदेश में कई आधार शामिल हैं, भले ही उनमें से एक को खारिज कर दिया जाए, धारा 5 ए में निहित अलगाव का सिद्धांत लागू हो जाता है। (पैरा 20, 23] [384-डी; 387-एफ]

ए. सोकाथ अली यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (2000) 7 एससीसी 148: [2000] 2 पूरक एससीआर 48; वशिष्ठ नारायण करवरिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1990) 2 एससीसी 629 1 [1990] 2 एससीआर 212; वकील सिंह बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं एक अन्य (1975) 3 एससीसी 545; हंसमुख बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (1981) 2 एससीसी 175: [1981] 1 एससीआर 353; गुजरात राज्य बनाम चमनताल मंजीभाल सोनी (1981) 2 एससीसी 24: [1981] 2 एससीआर 500; प्रकाश चंद्र मेहता बनाम आयुक्त और सचिव, केरल सरकार और अन्य (1985) पूरक एससीसी 144: [1985] एससीआर 697- पर भरोसा किया गया।

खुदीराम दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (1975) 2 एससीसी 81: [1975] 2 एससीआर 832; मदन लाल आनंद बनाम भारत संघ एवं अन्य। (1990) 1 एससीसी 81: [1989] 1 पूरक एससीआर 733; भारत और अन्य के लिए अटॉर्नी जनरल बनाम अमृतियल प्रजीवनदास और अन्य। (1994) 5 एससीसी 54: [1994] 1 पूरक एससीआर 1 – संदर्भित किया गया।

<u>प्रकरण कानून संदर्भ</u>

[1975] 2 एससीआर 832 संदर्भित किया गया पैरा 12

[1990] 2 एससीआर 212 भरोसा व्यक्त किया पैरा 15

[2000] 2 पूरक। एससीआर 48 भरोसा व्यक्त किया पैरा 15

(1975) 3 एससीसी 545 भरोसा व्यक्त किया पैरा 16

(1981] 1 एससीआर 353 भरोसा व्यक्त किया पैरा 17

(1981] 2 एससीआर 500 भरोसा व्यक्त किया पैरा 18

[1985] एससीआर 697 भरोसा व्यक्त किया पैरा 21

(1989) 1 पूरक एससीआर 733 संदर्भित किया गया पैरा 22

[1994] 1 पूरक एससीआर 1 संदर्भित किया गया पैरा 24

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2281/2014

रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 2060 /2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 18.03.2014 से।

मय

डब्ल्यू.पी. (सीआरएल.) नंबर 203/2015

विक्रम चौधरी, वरिष्ठ वकील, संग्राम एस सरोन, हर्षित सेठी, मनीष वर्मा, ऋषि सहगल, सुश्री प्रगति शर्मा, निखिल जैन, अपीलकर्ता के वकील।

सुश्री माधवी दीवान, सुश्री बीनू टम्टा, सुश्री रंजना नारायण, एस. वसीम ए. कादरी, सुश्री निधि खन्ना, बी. कृष्णा प्रसाद, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय ए.के. सीकरी, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। 1. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (इसके बाद "अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3(1) के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा निरूद्ध आदेश दिनांक 23.09.2009 पारित किया गया था। जिसके तहत अपीलकर्ता को हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया था। प्रारंभ में, इस आदेश को अपीलकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में रिट याचिका दायर करके पूर्व-निष्पादन चरण में चुनौती दी गई थी। उक्त याचिका पर विचार किया गया और प्रारंभ में पिरूद्ध आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी गई थी। हालाँकि, अंततः दिनांक 01.10.2013 के आदेश के तहत, रिट याचिका को अपीलकर्ता को अपने कानूनी उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। इसके बाद, अपीलकर्ता 18.11.2013 को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के सामने पेश हुआ जब वह हिरासत के आदेश के साथ तामील किया गया। हिरासत के उक्त आदेश के कार्यान्वयन में उन्हें भी हिरासत में लिया गया और केंद्रीय जेल, तिहाड़ में रखा गया।

21.11.2013 और 22.11.2013 को, अपीलकर्ता को हिरासत के आधार के साथ-साथ अनुवाद के साथ कुछ विश्वसनीय दस्तावेजों की प्रतियां भी प्रदान की गईं। अपीलकर्ता के अनुसार, दस्तावेजों का पूरा सेट, जिस पर प्रतिवादीगणो ने भरोसा किया था, प्रदान नहीं किया गया था। उन्होंने हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को 03.12.2013 को नजरबंदी

आदेश को रद्द करने या वैकल्पिक रूप से पूर्ण दस्तावेज/सूचना आपूर्ति करने का अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन दिया था, जिसके बाद दिनांक 06.12.2013 को एक और अभ्यावेदन आया। अपीलकर्ता के अनुसार, इन अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए प्रतिवादीगणो को अपीलकर्ता को तुरंत रिहा करने और दिनांक 23.09.2009 के हिरासत आदेश को रद्द करने के निर्देश के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। इस याचिका का उत्तरदाताओं ने विरोध किया था।

2. उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.03.2014 के निर्णय द्वारा रिट याचिका खारिज कर दी है। इस स्तर पर ही टिप्पणी की जा सकती है, हालाँकि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की इस दलील को स्वीकार कर लिया है कि हिरासत आदेश में एक विशेष आरोप के लिए प्रतिवादियों की ओर से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता हुई थी, इसने अभी भी अधिनियम की धारा 5ए में उल्लिखित आधारों के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करते हुए निरूद्ध के आदेश को बरकरार रखा है। संक्षेप में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐसे कई आधार थे जो हिरासत आदेश का आधार बने और भले ही किसी विशेष आधार से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हों, अलगाव के सिद्धांत को लागू करते हुए उस आधार को नजरअंदाज किया जा सकता है। शेष आधार पर हिरासत आदेश अभी भी टिकाऊ था।

3. उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त फैसले के खिलाफ की गई वर्तमान अपील में, अपीलकर्ता द्वारा यह दलील दी गई है कि आधार की पृथक्करणीयता का सिद्धांत, जो अधिनियम की धारा 5ए में निहित है, मौजूदा मामले पर लागू नहीं है। निरूद्ध आदेश केवल एक आधार पर पारित किया गया था, जिसके समर्थन में निरूद्ध आदेश के साथ संलग्न निरूद्ध करने के आधार में कुछ उदाहरण दिए गए थे जिन्हें अलग-अलग आधार नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि निरूद्ध आदेश का हिस्सा बनने वाले वे

उदाहरण वास्तव में बुनियादी तथ्यों के बजाय केवल अतिरिक्त विवरण या सहायक तथ्य थे जो निरूद्ध आदेश का अभिन्न अंग हैं और आधार बनाते हैं। यह मामले का वह पहलू है जिसकी वर्तमान मामले में जांच की आवश्यकता है।

4. उपरोक्त परिचयात्मक नोट के साथ, हम अब उक्त आदेश के समर्थन में निरूद्ध के आदेश के साथ-साथ निरूद्ध के आधार का जायजा ले सकते हैं।

5. निरूद्ध आदेश दिनांक 23.09.2009 दर्ज करता है कि प्रतिवादी नंबर 2 संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के संबंध में निरूद्ध आदेश पारित करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में उसे विदेशी मुद्रा के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोका जा सके। उक्त आदेश के समर्थन में भविष्य के आधार, 46 पृष्ठों में हैं, जिसमें विभिन्न गतिविधियों की गणना की गई है, जिसमें अपीलकर्ता विदेश से प्राप्त उपकरणों पर हवाला भुगतान करने और प्राप्त करने में लिप्त था; और अपीलकर्ता चांदनी चौक में अपने व्यावसायिक परिसर के साथ-साथ अशोक विहार में आवासीय परिसर से ऐसे हवाला भुगतान कर रहा था। इस आशय की सूचना मिलने पर अपीलकर्ता के व्यावसायिक स्थान पर तलाशी ली गई। 2,04,00,000/- रुपये की भारतीय मुद्रा के साथ-साथ विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ पाए गए और जब्त कर लिए गए। इसी प्रकार, से अपीलकर्ता के आवासीय परिसर से समान आपत्तिजनक दस्तावेजों के अलावा, 64,35,000/- रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। तलाशी के दौरान, विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए, जिनका विवरण संक्षेप में उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए कथनों के साथ दिया गया है। "निरूद्ध का आधार' उस सम्मन को भी संदर्भित करता है जो अपीलकर्ता को जारी किया गया था जिसके अनुसार उसका बयान दर्ज किया गया था और उक्त बयान का सार आधार में शामिल किया गया है। अपने बयान में अपीलकर्ता द्वारा दिए गए हवाला लेनदेन को रिकॉर्ड करने वाली विभिन्न स्वीकारोक्ति का भी उल्लेख किया गया है

बयान को वापस लेने पर भी ध्यान दिया गया है, कहा गया है कि विभाग द्वारा इस पर विचार किया गया था लेकिन इसे बाद में लिया गया विचार माना गया।

6. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में, निरूद्ध आदेश को चुनौती देने के लिए अपीलकर्ता द्वारा की गई याचिका के पृष्ठ 1 से 25 में शामिल कुछ विश्वसनीय दस्तावेजों को प्रदान करने में प्रतिवादीगणो की ओर से विफलता थी। 03.09.2009 को दर्ज किए गए पूरन चंद शर्मा के बयान में उल्लेख किया गया है। हिरासत के आधार में, पूर्ण चंद शर्मा के बयान को पैराग्राफ 37 से 41 तक संदर्भित किया गया है जिसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि 03.09.2009 को पूरन चंद शर्मा के खिलाफ की गई खोजों से पता चला था कि अपीलकर्ता पूर्वाग्रहपूर्ण हवाला व्यवहार में अगस्त, 2009 में भी शामिल रहा था। अपीलकर्ता के अनुसार, इन दस्तावेजों की गैर-आपूर्ति, जो बहुत महत्वपूर्ण थे, ने अपीलकर्ता को सलाहकार बोर्ड और केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण प्रतिनिधित्व करने के अपने मूल्यवान अधिकार से वंचित कर दिया और इस प्रकार, निरूद्ध आदेश को निष्फल कर दिया और भी अधिक, जब इन्हें इस संबंध में किए गए विशिष्ट अनुरोध के समर्थन में आपूर्ति नहीं की गई थी।

7. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति पर प्रतिवादीगणो द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया। हालाँकि, प्रतिवादीगणो ने तर्क दिया कि विचाराधीन दस्तावेज़ महत्वपूर्ण नहीं थे और इसलिए, उनकी आपूर्ति न करने से अपीलकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। प्रतिवादीगणो की इस दलील को उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है, जैसा कि निम्नलिखित चर्चा से स्पष्ट है:

> "7. हिरासत के आधारों में उपरोक्त स्पष्ट और सकारात्मक रुख के मद्देनजर, जवाबी हलफनामे और अतिरिक्त हलफनामे में इस रुख को स्वीकार करना संभव नहीं है कि पूरन चंद शर्मा की तलाशी के दौरान

उनके बयान दिनांक 3 सितंबर, 2009, वापसी दिनांक 4 सितंबर, 2009 और विभाग का पत्र दिनांक 9.9.2009 के अलावा जो दस्तावेज या सामग्री मिली है, पर विचार नहीं किया गया था। उक्त दावा निरूद्ध आदेश के पैराग्राफ 37, 38 और 41 में दिए गए विशिष्ट शब्दों और कथनों के विपरीत है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। पूछे जाने पर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि उनके पास 3 सितंबर, 2009 को पूरन चंद शर्मा के स्थान पर तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों या सामग्री की कोई प्रति नहीं है। हालाँकि, हमें पूरन चंद शर्मा के बयान दिनांक 3 सितंबर, 2009 की प्रति दिखाई गई थी। पूरन चंद शर्मा को एक विशिष्ट दस्तावेज का सामना करना पड़ा और जवाब में उन्होंने कहा कि यह प्रविष्टि पूरन चंद शन्ना और याचिकाकर्ता के बीच लेनदेन से संबंधित है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज़ यानी तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज़ जिसका सामना पूरन चंद शर्मा से कराया गया था और पूरन चंद शर्मा ने याचिकाकर्ता को फंसाया था। यह एक विश्वसनीय दस्तावेज़ था। अन्यथा भी यह एक प्रासंगिक दस्तावेज़ होगा। उक्त दस्तावेज़ को केवल तथ्यों का वर्णन या निरूद्ध के आधार पर तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आकस्मिक संदर्भ के रूप में नहीं माना जा सकता है। प्रविष्टि वाले दस्तावेज़ ने निरूद्ध के आधार के अनुच्छेद 37, 38 और 41 में किए गए दावों का आधार बनाया।"

8. इसके बावजूद, उच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि अपीलकर्ता को फंसाने वाले पूरन चंद शर्मा के मामले में जब्ती विवरण से संबंधित पैराग्राफ एक अलग आधार बनाते हैं, जो अलगाव के सिद्धांत के आवेदन पर अलग करने योग्य था, क्योंकि निरूद्ध आदेश अनेक आधारों पर आधारित था । इसके बाद, उच्च न्यायालय का आदेश निरूद्ध

आदेश में उल्लिखित विभिन्न आधारों को इंगित करता है और उन्हें अलग-अलग आधार मानता है। अपीलकर्ता का यह तर्क कि इस मामले में 'हिरासत के आधार' समग्र हैं और अलग नहीं हैं, इस न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों की सहायता से खारिज कर दिया गया है।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री चौधरी ने प्रस्तुत किया कि निरूद्ध का केवल एक ही आधार था जिसके आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया था, अर्थात्, 'उसे (यानी अपीलकर्ता को) किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकना। भविष्य में विदेशी मुद्रा के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए प्रतिकूल' और उसके निरूद्ध के आधार, जो कि उसके समर्थन में दिए गए थे, वास्तव में, उक्त आधार पर विभिन्न उदाहरण थे। इस दलील को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का हवाला दिया और तर्क दिया कि यह कई आधारों का वर्णन करता है जिन पर हिरासत का आदेश पारित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 3 इस प्रकार है:

"3. कुछ व्यक्तियों को निरूद्ध करने के आदेश देने की शक्ति -

(1) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई अधिकारी, जो उस सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो, उस सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त हो, या राज्य सरकार का कोई अधिकारी, उस सरकार के सचिव के पद से नीचे का नहीं, उस सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त, किसी भी व्यक्ति (एक विदेशी सहित) के संबंध में संतुष्ट होने पर, उसे कार्य करने से रोकने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा के संरक्षण या संवर्द्धन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या उसे रोकने की दृष्टि से कोई भी तरीका-

(i) तस्करी के सामान, या

(ii) माल की तस्करी पर दांव लगाना, या

(iii) तस्करी के माल के परिवहन या छुपाने या रखने में संलग्न होना, या

(iv) तस्करी के माल को परिवहन करने या छुपाने या रखने में संलग्न होने के अलावा अन्यथा व्यापार करना, माल की तस्करी करना या

(v) माल की तस्करी में लगे व्यक्तियों को शरण देना या माल की तस्करी को रोकना

ऐसा करना आवश्यक है, एक आदेश जारी करें जिसमें निर्देश दिया जाए कि ऐसे व्यक्ति को निरूद्ध किया जाए।

(2) जब किसी राज्य द्वारा हिरासत का कोई आदेश दिया जाता है। सरकार या राज्य सरकार द्वारा सशक्त किसी अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार, दस दिनों के भीतर, आदेश के संबंध में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगी।

(3) संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (5) के प्रयोजनों के लिए, निरोध आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उन आधारों की जानकारी, जिन पर आदेश दिया गया है, निरोध के बाद यथाशीघ्र किया जाएगा, लेकिन आम तौर पर पांच दिनों के बाद नहीं, और असाधारण परिस्थितियों में और इसके लिए निरूद्ध की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर लिखित रूप में कारण दर्ज किए जाने चाहिए।"

10. निवेदन यह है कि आदेश केवल एक आधार पर पारित किया गया था, अर्थात अपीलकर्ता की गतिविधियाँ विदेशी मुद्रा के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए प्रतिकूल थीं। उनके अनुसार, धारा 3 में उल्लिखित अन्य आधार वे हैं जो उप-धारा (1) के खंड (i) से (v)

में संदर्भित हैं जैसे माल की तस्करी, माल की तस्करी को बढ़ावा देना, आदि, लेकिन इनमें से कोई भी आधार निरूद्ध आदेश पारित करते समय लागू नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि ' निरूद्ध के आधार' में ही निरूद्ध में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा यह कहा गया था कि उसमें बताई गई तथाकथित गतिविधियाँ अपीलकर्ता और अन्य लोगों की गतिविधियों को 'संचयी रूप से इंगित' करती हैं जिनके साथ वह हवाला लेनदेन में जुड़ा हुआ था। उच्च न्यायालय में उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में भी यही स्थिति अपनाई गई थी। इसलिए, प्रतिवादीगण के अनुसार ' निरूद्ध के आधार' को संचयी रूप से भी पढ़ने की जरूरत है, जो स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि ये आधार समग्र थे और अलग नहीं थे। यह तर्क दिया गया कि ऐसी परिस्थितियों में, पृथक्करणीयता का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है। अपनी दलील के समर्थन में, उन्होंने ए. सोवकाथ अली बनाम भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। जहां अधिनियम की धारा 5-ए के आधार पर पृथक्करण के सिद्धांत की प्रयोज्यता के मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसे राज्य द्वारा लागू किया गया था, और दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किए गए इस न्यायालय के पहले के निर्णयों पर ध्यान दिया गया, जैसा कि उसमें शामिल निम्नलिखित चर्चा से स्पष्ट है: (एससीसी हेडनोट)

> "24. प्रकाश चंद्र मेहता बनाम कमिश्नर और सचिव, केरल सरकार [1985 पूरक एससीसी 144] पर भरोसा रखा गया है। यह एक ऐसा मामला था जहां हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा किए गए कबूलनामे को वापस लेने का हवाला हिरासत के आधार में नहीं दिया गया था। यह न्यायालय ने धारा 5-ए के मद्देनजर माना कि यदि मामले में उल्लिखित अन्य स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ कारकों के आधार पर व्यक्तिपरक संतुष्टि प्राप्त की गई है, तो दिमाग का उपयोग न करने के आधार पर हिरासत आदेश को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने माना :

"यदि बंदी द्वारा स्वीकारोक्ति में बताए गए तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए भी आधार में उल्लिखित अन्य स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ तथ्यों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो निरूद्ध के आदेश को केवल स्वीकारोक्ति से निकाले गए निष्कर्ष की अस्वीकृति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान मामले में अधिकारी कई कारकों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बंदी तस्करी में लगे हुए थे, जैसे, बंदी के कमरे में तलाशी और जब्ती और सोने के बिस्कुट की बरामदगी, बंदी द्वारा उन सोने के बिस्कुटों के आयात के बारे में समझाने में विफलता, गुप्त तरीके से सोने के बिस्कुट रखे गए थे, विभिन्न डीलरों के साथ संबंध और डीलरों के कर्मचारियों के बयान कि बंदी सोने की छड़ें आदि लेकर आते थे। ये सामग्रियां बंदी द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत दिए गए बयानों और स्वीकारोक्ति के अतिरिक्त थीं। इसलिए भले ही उन बयानों पर विचार नहीं किया जा सकता है जिन्हें इस तरह वापस ले लिया गया था, फिर भी इकबालिया बयान से स्वतंत्र अन्य तथ्य हैं जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, जिससे अधिकारियों को संतुष्टि मिल सकती है। COFEPOSA अधिनियम की धारा 5-ए के मद्देनजर हिरासत के अन्य आधारों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सामग्री थी, भले ही अधिकारियों द्वारा स्वीकारोक्ति को वापस लेने पर विचार नहीं किया गया हो।"

25. अगली निर्भरता मदन लाल आनंद बनाम भारत संघ [(1990) I एससीसी 81] पर है। यह मामला भी वापसी न करने के संदर्भ में है और धारा 5-ए के संदर्भ में और प्रकाश चंद्र मामले पर भरोसा करते हुए [1985 पूरक एससीसी 144] यह आयोजित किया गया था: (एससीसी पृष्ठ 91, पैरा 29)

"29. वर्तमान मामले में, भले ही यह मान लिया जाए कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत निरूद्ध में लिए गए इकबालिया बयान से संबंधित आधार एक अस्वीकार्य आधार था क्योंकि बाद में इकबालिया बयान को वापस लेने पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया था, फिर भी तो इससे निरूद्ध आदेश ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इस न्यायालय की राय में, ऐसा हिरासत का आदेश ऐसे प्रत्येक आधार पर अलग से दिया गया माना जाएगा। इसलिए, अस्वीकार्य आधार को छोड़कर भी, हिरासत के आदेश को उचित ठहराया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में बंदी की दलील को खारिज कर दिया है और हमारी राय में यह सही है।"

26. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने वशिष्ठ नारायण करवरिया बनाम यूपी राज्य [(1990) 2 एससीसी 629] पर भरोसा जताया। इस न्यायालय ने कहा: (एससीसी पृ. 633-34, पैरा 11)

"11. श्री दलवीर भंडारी ने अधिनियम की धारा 5-ए पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि निरूद्ध के आदेश को केवल इस आधार पर अमान्य या निष्क्रिय नहीं माना जाना चाहिए कि कुछ बाहरी सामग्रियों को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था क्योंकि उन कथित बाहरी सामग्रियों को इस आक्षेपित आदेश की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिसे निरूद्ध के आधार पर निर्धारित सामग्री पर कायम रखा जा सकता है। प्रकाश चंद्र मेहता बनाम कमिश्नर और सचिव, केरल सरकार में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, जिसमें यह यह देखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत 'आधार' का मतलब केवल तथ्यात्मक अनुमान नहीं है, बल्कि इसका मतलब तथ्यात्मक

अनुमान और तथ्यात्मक सामग्री है, प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में निरूद्ध के आधार में निर्धारित तथ्यात्मक सामग्री अकेले ही कारण बनी। बंदी को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से आदेश पारित करना। हम उपरोक्त प्रस्तुतिकरण में कोई बल नहीं देख पा रहे हैं। धारा 5-ए यह प्रदान करती है कि जहां बंदी की विभिन्न गतिविधियों को कवर करने वाले दो या दो से अधिक आधार हैं, प्रत्येक गतिविधि अपने आप में एक अलग आधार है और यदि इनमें से कोई एक आधार अस्पष्ट, अस्तित्वहीन, प्रासंगिक नहीं है, ऐसे व्यक्ति से जुड़ा नहीं है या लगभग जुड़ा नहीं है या किसी भी अन्य कारण से अमान्य है, तो इससे निरूद्ध का आदेश ख़राब नहीं होगा।"

इस मामले में राज्य की ओर से पूर्वोक्त निर्णयों पर विचार किया गया। श्री चौधरी ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला वशिष्ठ नारायण करवरिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में उल्लिखित श्रेणी में आता है।

11. उपरोक्त निर्णयों पर ध्यान देने के बाद, ए. सोकाथ अली मामले में न्यायालय ने पैरा 27 में अपना निष्कर्ष निम्नानुसार दर्ज किया:

"27. सबसे पहले, हम पाते हैं कि धारा 5-ए के तहत पृथक्करण का प्रश्न राज्य द्वारा किसी भी प्रति-शपथ पत्र में नहीं उठाया गया है, लेकिन अन्यथा भी यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। धारा 5-ए वहां लागू होता है जहां निरूद्ध एक से अधिक आधारों पर आधारित होती है, न कि वहां जहां यह एक ही आधार पर आधारित होती है। प्रेम प्रकाश बनाम भारत संघ [Crl. A. No. 1996 का 170 दिनांक 7-10-1996) (नीचे पृष्ठ 163 पर देखें)] के असूचित निर्णय में भी इस न्यायालय का

यही निर्णय है, के. सत्यनारायण सुबुद्धि बनाम भारत संघ [1991 पूरक (2) एससीसी 153] पर भरोसा करते हुए 7-10-1996 को फैसला सुनाया गया। वर्तमान मामले में हम वास्तव में पाते हैं कि यह एक समग्र आधार का मामला है। निरूद्ध के आधार की विभिन्न संख्याएं केवल दस्तावेज़ के विवरण के साथ तथ्यों को बताने वाले पैराग्राफ हैं जिन पर भरोसा किया जा रहा है लेकिन तथ्यात्मक रूप से, निरूद्ध का आदेश एक आधार पर आधारित है, जो निरूद्ध के आधार के आधार (1)(xvi) द्वारा प्रकट होता है जिसे हम यहां पहले ही उद्धृत कर चुके हैं। इस प्रकार इस मामले के तथ्यों पर धारा 5-ए का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है।"

12. विद्वान वकील ने खुदीराम दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें 'आधार' शब्द का अर्थ निर्दिष्ट और समझाया गया है। इसका पैरा 15, जिस पर विद्वान वकील ने बहुत अधिक भरोसा किया था, इस प्रकार है:

"15. अब, इस प्रस्ताव पर शायद ही कोई विवाद हो सकता है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ सामग्री है जो अत्यधिक हानिकारक चरित्र की है और निरूद्ध की वस्तु के साथ संबंध और प्रासंगिकता रखती है, और व्यक्तिपरक संतुष्टि के समय के साथ निकटता रखती है निरूद्ध के आदेश को आधार बनाते हुए, अदालत के लिए यह निष्कर्ष निकालना वैध होगा कि ऐसी सामग्री ने जिला मजिस्ट्रेट को उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि तक पहुंचने में प्रभावित किया होगा और ऐसे मामले में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के इस बेदाग बयान को स्वीकार करने से इंकार कर देगा कि उसने ऐसी सामग्री को ध्यान में नहीं रखा और इसे विचार से बाहर रखा। यह प्राथमिक बात है

कि मानव मस्तिष्क खंडों में कार्य नहीं करता है। जब यह विभिन्न स्रोतों से इंप्रेशन प्राप्त करता है, तो यह प्रभाव की समग्रता है जो निर्णय लेने में जाती है और प्रभाव का विश्लेषण और विच्छेदन करना और भविष्यवाणी करना संभव नहीं है कि कौन से प्रभाव निर्णय लेने में गए और कौन से नहीं। न ही विशेष परिस्थितियों द्वारा बनाई गई धारणा को मिटाना कोई आसान अभ्यास है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में ऐसी धारणा के प्रभाव को बाहर रखा जा सके। इसलिए, ऐसे मामले में जहां जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत सामग्री ऐसे चरित्र की है जो पूरी संभावना है कि किसी भी उचित इंसान के निर्णय को प्रभावित कर सकती है, अदालत जिला मजिस्ट्रेट के आईपीएसी दीक्षित को स्वीकार करने में सबसे अधिक अनिच्छुक होगी। वह इतना प्रभावित नहीं था और एक फोर्टियोरी था, अगर ऐसी सामग्री का खुलासा बंदी को नहीं किया गया, तो निरूद्ध का आदेश रद्द हो जाएगा, दोनों इस आधार पर कि जिला मजिस्ट्रेट की व्यक्तिपरक संतुष्टि को प्रभावित करने वाले सभी बुनियादी तथ्य और सामग्री को सूचित नहीं किया गया था। बंदी को और इस आधार पर भी कि बंदी को नजरबंदी के आदेश के खिलाफ प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था।

13. श्री चौधरी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) की सहायता से एक और भावुक दलील भी दी। उन्होंने तर्क दिया कि जब संविधान के अनुच्छेद 22(5) में निहित संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन होता है, तो अधिनियम की धारा 5ए के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जा सकता है। उनके अनुसार, ऐसी परिस्थितियों में, हिरासत आदेश शुरू से ही अमान्य होगा और इसलिए, अधिनियम की धारा एसए की आलोचना करते हुए ऐसे आदेश को बनाए रखने का सवाल ही नहीं उठता।

14. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने आक्षेपित निर्णय में निहित चर्चा को बड़े पैमाने पर पढ़ा और प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने इस मामले के तथ्यों पर, पृथक्करण के सिद्धांत को सही ढंग से लागू किया है, जिसे अधिनियम की धारा 5 ए के तहत वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है।

15. इसमें शामिल मुद्दे की प्रकृति और उस पर दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों की एक झलक, यह स्पष्ट कर देती है कि जहां तक कानूनी स्थिति का सवाल है, इस संबंध में कोई विवाद नहीं है, न ही कोई विवाद हो सकता है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि यदि निरूद्ध का आदेश एक से अधिक आधारों पर आधारित है, एक-दूसरे से स्वतंत्र है, तो निरूद्ध का आदेश तब भी कायम रहेगा, भले ही पाए गए आधारों में से कोई एक गैर-मौजूदा या कानूनी रूप से अस्थिर हो (देखे- वशिष्ठ नारायण करवरिया)। दूसरी ओर, यदि निरूद्ध आदेश एक समग्र आधार पर स्थापित किया गया है, हालांकि इसमें विभिन्न प्रजातियां या उप-शीर्ष शामिल हैं, तो ऐसे आधार पर गलती पाए जाने पर निरूद्ध आदेश रद्द कर दिया जाएगा (देखें ए. सोकाथ अली)। इस प्रकार, मौजूदा मामले में, अपील का नतीजा इस सवाल पर निर्भर करता है कि क्या निरूद्ध का आदेश अकेले एक आधार पर आधारित है या यह कई आधारों का मामला है, जिस पर विवादित निरूद्ध आदेश पारित किया गया था।

16. हिरासत आदेश का उचित विश्लेषण करने के लिए, हमें पहले उस अर्थ को समझना होगा जो अधिनियम की धारा एसए में निहित अभिव्यक्ति 'आधार' के लिए जिम्मेदार है। वकील सिंह बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य मामले में, अभिव्यक्ति 'आधार' को निम्नलिखित अर्थ दिया गया था:

> "29. हमने इस फैसले में पहले ही निरूद्ध के आधारों का विवरण पूरी तरह से पुन: प्रस्तुत कर दिया है। समग्र रूप से पढ़ें तो वे निरूद्ध में लिए गए लोगों को उनकी निरूद्ध आधारों के बारे में जानकारी देने के लिए

यथोचित रूप से स्पष्ट और आत्मनिर्भर प्रतीत होते हैं। संक्षिप्त नाम F.I.U. इन आधारों में चार बार आता है, लेकिन हर बार पाक के साथ संयोजन में, और दो बार "पाक अधिकारी" शब्दों के साथ। शब्दों का संयोजन और जिस संदर्भ में F.I.U होता है वह इसके अभिप्राय को पर्याप्त रूप से समझने योग्य बनाता है। "आधार "अधिनियम की धारा 8(1) के चिंतन के अंतर्गत सामग्री का अर्थ है' जिस पर निरूद्ध का आदेश मुख्य रूप से आधारित है। तथ्यों के निष्कर्ष के अलावा, "आधार" में एक तथ्यात्मक घटक भी होता है। उनमें सार और सार शामिल होना चाहिए प्राथमिक तथ्य, लेकिन सहायक तथ्य या साक्ष्य संबंधी विवरण नहीं। आधार के सभी आवश्यक घटकों के संचार की इस आवश्यकता का वर्तमान मामले में अनुपालन किया गया था। तथ्यात्मक विवरणों से भिन्न मूल तथ्य, बंदी को संप्रेषित की गई सामग्री में शामिल किये गये थे। उसे कुख्यात पाक एजेंट और कूरियर (जुंबियान निवासी मियां रेहम) का नाम बताया गया, जिसके माध्यम से वह भारतीय सेना के बारे में जानकारी दे रहा था। उन्हें पाकिस्तान के उन स्थानों के बारे में जानकारी दी गई, जहां वे जा रहे थे। उन्हें आगे बताया गया कि इस जानकारी की आपूर्ति के बदले उन्हें पाकिस्तान से पैसे मिल रहे थे। उन्हें प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने के लिए और कुछ भी सूचित करने की आवश्यकता नहीं थी। जिन तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया, वे बुनियादी तथ्य नहीं थे और उनके गैर-प्रकटीकरण से याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व करने के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसा कि उस संचार में बताया गया था जिसके तहत निरूद्ध में लिए गए लोगों को हिरासत में लेने के आधार बताए गए थे, उन तथ्यात्मक विवरणों को

निरूद्ध में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा रोक दिया गया था क्योंकि उनकी राय में, उनका खुलासा सार्वजनिक हित के खिलाफ होता।"

17. एक बार फिर, इसी पहलू को हंसमुख बनाम गुजरात राज्य और अन्य में विधिवत समझाया गया।' निम्नलिखित शब्दों में:

"18.... इन निर्णयों से यह स्पष्ट है कि जबकि अनुच्छेद 22(5) में और उस मामले के लिए, COFEPOSA की धारा 3(3) में अभिव्यक्ति "आधार" में न केवल तथ्य के निष्कर्ष शामिल हैं, बल्कि सभी 'बुनियादी तथ्य' जिन पर ये निष्कर्ष आधारित हैं, वे सहायक तथ्यों या इन बुनियादी तथ्यों के अतिरिक्त विवरणों से भिन्न हैं। 'बुनियादी तथ्य' जो 'आधार' के आवश्यक तथ्यात्मक घटक हैं और उनके आगे के विवरण या सहायक विवरण के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। जबकि 'बुनियादी तथ्य' 'आधार' का अभिन्न अंग हैं, COFEPOSA की धारा 3(3) के अनुसार, "निरूद्ध के बाद, जितनी जल्दी हो सके, निरूद्ध में लिए गए व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए, आमतौर पर पांच दिन से ज्यादा नहीं, और असाधारण परिस्थितियों में और कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए निरूद्ध की तारीख से 15 दिनों से ज्यादा नहीं", खुदी राम (एआईआर 1975 एससी एस 50) के मामले में अनुच्छेद 22(5) में उल्लिखित दूसरी संवैधानिक अनिवार्यता के अनुपालन में उन आधारों के अतिरिक्त विवरण, यथाशीघ्र, व्यावहारिक रूप से, उचित तरीके से निरूद्ध किये जाने की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी मामले में बंदी को बताए गए हिरासत के तथाकथित आधारों में बुनियादी या प्राथमिक तथ्यों का अभाव है, जिस पर उसमें बताए गए तथ्य के निष्कर्ष आधारित हैं, और इस कमी को पूरा नहीं किया गया है और धारा 3(3) में निर्दिष्ट अवधि के

भीतर बंदी को सूचित किया गया है चूक हिरासत की वैधता के लिए घातक होगी। हालाँकि, यदि सूचित किए गए आधार विस्तृत हैं और उनमें सभी "बुनियादी तथ्य" शामिल हैं, लेकिन "बुनियादी तथ्यों" के सभी विवरणों या विवरणों को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक नहीं हैं, तो ऐसे विवरण, हिरासत में लिए जाने पर भी बंदी को, यदि उसके द्वारा मांगी जाती है, उचित समय के भीतर, उचित शीघ्रता के साथ; प्रदान किए जाने चाहिए। इस तरह के विवरण या अतिरिक्त विवरण की आपूर्ति के लिए आवश्यक "उचित अभियान के अनुरूप उचित समय" क्या है, यह विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तथ्य का प्रश्न है। किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में, यदि ऐसे अतिरिक्त विवरणों की आपूर्ति के लिए लिया गया समय, आधारों के संचार के लिए क़ानून द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से थोड़ा अधिक है, तो इसे अभी भी "उचित" माना जा सकता है, जबकि दूसरे मामले के तथ्यों में, यहां तक कि 15 दिनों से अधिक की देरी भी अनुचित हो सकती है, और खुदी राम के मामले (उपरोक्त) में बताई गई दूसरी संवैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन हो सकती है।"

18. इस विषय पर कानून को स्पष्ट करने वाला एक अन्य निर्णय, गुजरात राज्य बनाम चमनलाल मंजीभाई पुत्र है। इस पहलू पर निम्नलिखित चर्चा नीचे उद्धृत की गई गया है:

"2. उच्च न्यायालय को लगता है कि धारा 5-ए इस बात पर विचार करती है कि केवल एक ही आधार होना चाहिए जो अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन से संबंधित हो और यदि वह आधार अप्रासंगिक है और अन्य आधार जो किसी अन्य विषय से संबंधित हैं- मामला स्पष्ट और विशिष्ट है, निरूद्ध को ख़राब नहीं माना जाएगा। हमारी राय में, उच्च न्यायालय का

तर्क उचित सम्मान के साथ सवाल उठाने जैसा है क्योंकि अधिनियम की धारा 3 के तहत हिरासत केवल तस्करी और सभी को रोकने के उद्देश्य से है चाहे एक या अधिक आधार हों, वे केवल तस्करी की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित होंगे और हम किसी अन्य अलग आधार की कल्पना नहीं कर सकते हैं जो तस्करी के अलावा अन्य मामलों से निपट सके क्योंकि तस्करी का कार्य कई गतिविधियों को कवर करता है, जिनमें से प्रत्येक निरूद्ध का एक अलग आधार बनता है और अधिनियम तस्करी के अलावा किसी अन्य कार्य से संबंधित नहीं है। दरअसल, यदि धारा 5-ए के संबंध में उच्च न्यायालय की व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो धारा एस-ए निरर्थक हो जाएगी। धारा 5-ए की व्याख्या करते समय उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"लेकिन वर्तमान मामले में व्यक्तिपरक संतुष्टि एक आधार पर आधारित है, वह है, वर्तमान याचिकाकर्ता को माल की तस्करी से रोकना और उस आधार के समर्थन में विभिन्न बयानों पर भरोसा किया गया है और इन सभी बयानों पर विचार करने की समग्रता के परिणामस्वरूप निरूद्ध में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि जब उसने निरूद्ध के आदेश को पारित किया। अब निरूद्ध में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा विचार की गई परिस्थितियों की इन समग्रता के लिए, यदि कोई अप्रासंगिक या अस्थिर तत्व व्यक्तिपरक संतुष्टि की प्रक्रिया में प्रवेश कर गया है, तो व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचने की प्रक्रिया व्यापक होने के कारण, उक्त तत्व व्यक्तिपरक संतुष्टि की पूरी प्रक्रिया को परेशान कर देगा और परिणामस्वरूप, अगर एक बयान जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, वह हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की दिमाग की आंखों के सामने

आ जाए, तो यह आसानी से देखा जा सकता है कि उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि खराब हो जाएगी। और इसका अंतिम निर्णय सामग्री के उस हिस्से पर निर्भर करेगा जो अप्रासंगिक है।"

उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई तर्क की प्रक्रिया हमारे लिए बिल्कुल समझ से परे है। यह स्पष्ट है कि जब भी तस्करी के आरोप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लगाए जाते हैं जिसे आगे की तस्करी को रोकने के लिए निरूद्ध में लेने की मांग की जाती है, तो तस्करी के सामान के सामान्य उद्देश्य के साथ एक कार्य या कई कार्य होते हैं जिन्हें अधिनियम के द्वारा रोकने की मांग की जाती है। इसलिए, यह कहना सही नहीं होगा कि अधिनियम का उद्देश्य निरूद्ध का आधार बनता है। यदि ऐसा है, तो किसी भी मामले में निरूद्ध किये जाने का कोई अन्य आधार नहीं हो सकता, सिवाय उस आधार के जो तस्करी से संबंधित है। हमारी राय में, यह न तो अधिनियम का उद्देश्य है और न ही ऐसे उद्देश्य को उस भाषा से वर्णित किया जा सकता है जिसमें धारा 5-ए निहित है। अधिनियम में यह प्रावधान है कि जहां निरूद्ध किये गए लोगों की एक अवधि या अवधि में फैली विभिन्न गतिविधियों को कवर करने के लिए कई आधार हैं, वहां प्रत्येक गतिविधि अपने आप में एक अलग आधार है और यदि इनमें से एक आधार अप्रासंगिक, अस्पष्ट या अनिर्दिष्ट है, तो इससे निरोध का आदेश ख़राब नहीं होगा। धारा 5-ए को लागू करने का कारण यह था कि कई उच्च न्यायालयों ने यह विचार किया कि जहां निरूद्ध के आदेश में कई आधारों का उल्लेख किया गया है और उनमें से एक या तो अस्पष्ट या अप्रासंगिक पाया जाता है तो पूरा आदेश ख़राब हो जाता है क्योंकि ऐसा नहीं किया जा सकता है। यह निर्धारित किया जाना चाहिए

कि प्राधिकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि किस हद तक अस्पष्ट या अप्रासंगिक आधार से प्रभावित हो सकती है। इन निर्णयों के आधार को विस्थापित करने के लिए संसद ने धारा 5-ए को अधिनियमित किया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि भले ही एक आधार अप्रासंगिक हो लेकिन अन्य आधार स्पष्ट और विशिष्ट हैं जो स्वयं निरूद्ध के आदेश को ख़राब नहीं करेंगे..."

19. उपर्युक्त निर्णयों से, निरूद्ध के आदेश का आधार बनने वाले 'आधार' क्या हैं, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन आसानी से समझा जा सकता है। पहले उदाहरण में, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि ये आधार 'बुनियादी तथ्य' हैं जिन पर निष्कर्ष स्थापित किए जाते हैं और ये सहायक तथ्यों या इन बुनियादी तथ्यों के अतिरिक्त विवरणों से भिन्न होते हैं। पूर्वोक्त से, यह स्पष्ट है कि प्रत्येक 'बुनियादी तथ्य एक आधार और उसके समर्थन में विवरण का गठन करेगा या विवरण सहायक तथ्य होंगे या उक्त बुनियादी तथ्यों के अतिरिक्त विवरण होंगे जो' आधार का अभिन्न अंग होंगे। अधिनियम की धारा 3 में 'आधार' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अधिनियम में कोई अन्य प्रावधान 'आधार' को परिभाषित नहीं करता है। धारा 3(3) निरूद्ध के आदेश के संचार से संबंधित है और कहती है कि 'आधार' जिस पर आदेश दिया गया है, निरूद्ध का आदेश जारी होते ही बंदी को सूचित किया जाएगा और उस समय सीमा को तय करता है जिसके भीतर इस तरह के निरूद्ध आदेश को पारित किया जाना है। यहां अभिव्यक्ति 'आधार' का उपयोग किया जाता है और यही कारण है कि विस्तृत आधार जिस पर निरूद्ध आदेश पारित किया जाता है, बंदी को प्रदान किया जाता है। विभिन्न परिस्थितियां जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत दिए गए हैं, जिसके आधार पर निरूद्ध का आदेश पारित किया जा सकता है, आधार नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत, चमनतल मंजीभाई सोनी का मामला स्पष्ट करता है कि अधिनियम का केवल एक ही उद्देश्य है, अर्थात् तस्करी को

रोकना और अन्य सभी आधार, चाहे एक या अधिक हों, तस्करी की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित होंगे। इससे पता चलता है कि अलग-अलग उदाहरणों को अलग-अलग 'आधार' के रूप में माना जाएगा क्योंकि वे बुनियादी तथ्यों का गठन करते हैं जो उन्हें अनिवार्य रूप से 'आधार' का तथ्यात्मक घटक बनाते हैं और उन उदाहरणों के संबंध में जो अतिरिक्त विवरण दिए गए हैं वे सहायक विवरण हैं। हमारा यह दृष्टिकोण मिलता है वकील सिंह के मामले में चर्चा से इसे बल मिला जहां 'आधार' को "सामग्री के रूप में संदर्भित किया जाता है जिस पर निरूद्ध का आदेश मुख्य रूप से आधारित है"। न्यायालय ने यह भी बताया कि इन 'आधारों' में प्राथमिक तथ्यों का सार और सार होना चाहिए, लेकिन सहायक तथ्य या साक्ष्य संबंधी विवरण नहीं।

20. जब हम उपरोक्त परीक्षण को इस मामले के तथ्यों पर लागू करते हैं, तो हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत होते हैं कि निरूद्ध का आदेश कई आधारों पर आधारित है, क्योंकि विभिन्न विभिन्न अधिनियमों का उल्लेख किया गया है, जो अलग-अलग आधार बनाते हैं। जिसके आधार पर निरूद्ध किये जाने वाले प्राधिकारी ने यह राय बनाई कि अपीलकर्ता को निरूद्ध में रखना वांछनीय था। उच्च न्यायालय ने निरूद्ध के आदेश का विच्छेदन किया है, जो हमें लगता है कि आक्षेपित निर्णय के पैरा 11 और 12 में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया सही अभ्यास है और इसलिए, हम इसे पुन: प्रस्तुत करते हैं:

> "11. इसलिए, हम इस स्तर पर निरूद्ध आदेश में उल्लिखित आधारों का उल्लेख करना चाहेंगे। पैराग्राफ 1 में निरूद्ध आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने व्यावसायिक परिसर से विदेश से प्राप्त निर्देशों पर हवाला भुगतान करने और प्राप्त करने में लिप्त रहा है। चांदनी चौक में और एसएफएस फ्लैट, अशोक विहार में निवास। पैराग्राफ 2 में, यह कहा गया है कि 15 अक्टूबर, 2008 को दोनों परिसरों की तलाशी ली गई और 2,04,00,000/- रुपये की भारतीय मुद्रा और तीन मोबाइल फोन जब्त किए

गए। व्यावसायिक परिसर से 64,35,000/- रुपये की भारतीय मुद्रा और उनके आवासीय परिसर से दस्तावेज जब्त किए गए। याचिकाकर्ता के कर्मचारी शंकर उर्फ मीठा लाल का बयान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (संक्षेप में फेमा) की धारा 37 के तहत दर्ज किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का मुख्य कार्य दुबई में स्थित सुल्तान भाई, मामा @मनु, मिठू भाई, हिरानी और जब्बार भाई के निर्देशों पर भारत में भुगतान प्राप्त करना और करना था। शंकर ने जब्त किए गए दस्तावेजों के समूह में उल्लिखित आंकड़ों को डिकोड किया। उन्होंने आगे कहा था कि याचिकाकर्ता दुबई से निर्देश पर प्रति दिन 2 करोड़ रुपये का हवाला भुगतान कर रहा था और प्राप्त कर रहा था और पिछले तीन महीनों में 180 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त और किया। निरूद्ध आदेश में फेमा की धारा 37 के तहत दर्ज राम चंद गुप्ता, अमित जैन, अजय मिश्रा, पवन कुमार पांडे और विकेश कुमार के बयानों का भी उल्लेख किया गया है और उनसे निष्कर्ष निकाले गए हैं।

12. निरूद्ध आदेश में याचिकाकर्ता की बेटी यानी सुश्री कृष्णा जैन के बयान का सार उल्लेख किया गया है जो याचिकाकर्ता के निवास से जब्त किए गए 64.35 लाख रुपये के संबंध में फेमा की धारा 37 के तहत दर्ज किया गया है। 16 दिसंबर, 2008 और 22 दिसंबर, 2008 को फेमा की धारा 37 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयान, जो भारत में विभिन्न व्यक्तियों के लिए विदेश से व्यवस्थित विदेशी मुद्रा का विवरण और विभिन्न विवरणों को डी-कोड करने का विवरण देता है, को महत्व दिया गया है। निरूद्ध आदेश में फेमा की धारा 37 के तहत राजीव कुमार, जितेंद्र कुमार वर्मा और राज कुमार बिंदल के बयानों और विभिन्न व्यक्तियों

द्वारा दिए गए बयानों का भी उल्लेख है जिनके बयान फेमा की धारा 37 के तहत दर्ज किए गए थे, आदि। 17 दिसंबर, 2009 को विभिन्न परिसरों में तलाशी और उक्त तलाशी में नकदी की जब्ती सहित जब्ती और कपिल जिंदल, कन्हैया लाल, राज कुमार अग्रवाल, कांति लाल प्रजापति, अनिल अग्रवाल आदि के बयानों पर स्पष्टीकरण और भरोसा मिलता है। विभिन्न मोबाइल फोन का विवरण दर्ज किया गया है। आदेश में विभाग द्वारा 24 अप्रैल, 2009 को मुरलीधर के ठिकानों पर की गई तलाशी का जिक्र है, जिसके परिणामस्वरूप दस्तावेज और नकदी जब्त की गई थी। अलग-अलग तारीखों पर भरत कुमार का बयान दर्ज किया गया, इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था लेकिन वह पेश नहीं हुआ।"

21. वास्तव में, इसी तरीके से, मामले पर विचार किया गया और इस न्यायालय द्वारा प्रकाश चंद्र मेहता बनाम आयुक्त और सचिव, केरल सरकार और अन्य के मामले में निरूद्ध आदेश को बरकरार रखा गया, जैसा कि निम्नलिखित चर्चा से स्पष्ट है:

"71. धारा 5-ए में कहा गया है कि जब निरूद्ध का आदेश दो या दो से अधिक आधारों पर किया गया है, तो निरूद्ध के ऐसे आदेश को ऐसे प्रत्येक आधार पर अलग से बनाया गया माना जाएगा और तदनुसार यदि एक अप्रासंगिक या एक अस्वीकार्य आधार था इस बात को ध्यान में रखा गया कि निरोध आदेश ख़राब नहीं होगा।

Xx XX XX

75. वर्तमान मामले में, निरूद्ध का आधार निरूद्ध किये जाने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि है कि निरूद्ध में लिए गए व्यक्ति को विदेशी मुद्रा के संरक्षण या वृद्धि के लिए हानिकारक किसी भी तरीके से कार्य करने से

रोकने की दृष्टि से या निरूद्ध में लिए गए व्यक्ति को रोकने की दृष्टि से, अन्य बातों के साथ-साथ, तस्करी के माल के परिवहन या छुपाने या रखने में संलग्न होने, या तस्करी के माल के परिवहन या छुपाने या रखने में संलग्न होने के अलावा अन्यथा तस्करी के सामान से निपटने के लिए बंदी की निरूद्ध आवश्यक है। यह संतुष्टि कई कारकों से निष्कर्ष के रूप में निकाली गई थी। इनका अलग से उल्लेख किया गया है। उनमें से एक विवाद है लेकिन उसके बाद की गई वापसी पर ध्यान दिए बिना इस आधार पर विचार किया गया। लेकिन संतुष्टि का अनुमान कई कारकों से लगाया गया था जो पहले गिनाए जा चुके हैं। हमें यह जांचना होगा कि क्या अगर स्वीकारोक्ति में बताए गए तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए, तब भी इस मामले में उल्लिखित अन्य स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ तथ्यों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अर्थात्, 60 सोने के बिस्कुटों की तलाशी के बाद जब्ती का तथ्य, जो निस्संदेह पिता का था और उसने स्वीकार किया था कि वह उसका है जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और दूसरे अन्य समूहों और संगठनों से जुड़े कागजात की जब्ती। प्रताप सेत और अन्य जिन्हें पिता द्वारा सोना बेचा गया है, प्रासंगिक आधार हैं जिससे धारा 3 (i) (iii) और 3(1)(iv) के प्रयोजन के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए उचित रूप से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हमारी राय है कि केवल स्वीकारोक्ति से निकाले गए निष्कर्ष को अस्वीकार करने से विवादित आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। एक ही तर्क को थोड़ा अलग रंग में प्रस्तुत किया गया था, अर्थात्, निरूद्ध किये जाने वाले प्राधिकारी द्वारा वापसी के तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए था और न्यायालय को यह नहीं पता था

कि उस पर विचार किया गया था, निरूद्ध में लेने वाले प्राधिकारी किस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे। इस विवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमें आधार की पर्याप्तता से संबंधित नहीं है। हम संबंधित है कि क्या ऐसी प्रासंगिक सामग्रियां हैं जिन पर उक्त अधिनियम की धारा 3(1) में उल्लिखित आधारों पर निरूद्ध में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा उचित विश्वास या दोषसिद्धि पर विचार किया जा सकता है। निरूद्ध आदेश पारित करने के चरण में अन्य आधारों पर विचार किया जाना चाहिए था या नहीं, यह प्रासंगिक नहीं है। अत: यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि यही स्थिति है तो अधिनियम की धारा 5-ए के मद्देनजर निरूद्ध के इस आधार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सामग्री थी।"

22. इसके बाद न्यायालय ने चमनलाल मंजीभाई सोनी (पहले से ही ऊपर उल्लेखित) में अपने पहले के फैसले पर मदन लाल आनंद बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में समान तरीके से चर्चा की।

23. इस प्रकार, हम अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हैं कि, वर्तमान मामले में, निरूद्ध आदेश केवल एक आधार पर आधारित है। एक बार जब यह पाया जाता है कि निरूद्ध आदेश में कई आधार शामिल हैं, भले ही उनमें से एक को खारिज कर दिया जाए, धारा 5 ए में निहित अलगाव का सिद्धांत लागू हो जाता है।

24. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील का अन्य तर्क यह था कि एक बार संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन होने पर अधिनियम की धारा 5 ए के प्रावधान लागू नहीं होंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 22(5) इस प्रकार है:

"अनुच्छेद 22(5) जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत दिए गए आदेश के अनुसरण में निरूद्ध किया

जाता है, तो आदेश देने वाला प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, ऐसे व्यक्ति को उन आधारों के बारे में सूचित करेगा जिन पर आदेश पारित किया गया है और उसे आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का यथाशीघ्र अवसर प्रदान करेगा।"

यह प्रावधान उन आधारों की जानकारी देने का आदेश देता है जिन पर निरूद्ध का आदेश पारित किया गया है और उसे आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान किया जाता है। मौजूदा मामले में, पूरन चंद शर्मा के बयान वाले दस्तावेज़ नहीं दिए गए थे और इसी कारण से, उच्च न्यायालय ने सही माना कि आदेश के समर्थन में प्रतिवादियों द्वारा इस तरह के आधार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि यदि अन्य आधार हैं जिन पर निरूद्ध आदेश को कायम रखा जा सकता है, तो पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि अधिनियम की धारा 5ए के प्रावधानों को बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता है। इस तरह के तर्क को खारिज करते समय, यह बताना पर्याप्त होगा कि अधिनियम की धारा 5ए की संवैधानिक वैधता को इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी और भारत के अटॉर्नी जनरल और अन्य बनाम अमृतलाल प्रजीवनदास और अन्य के मामले में संविधान के अनुच्छेद 22(5) के आलोक में धारा 5ए के प्रावधानों पर चर्चा के बाद खारिज कर दिया गया था। अतः यह तर्क अपीलार्थी के पास उपलब्ध नहीं है।

25. परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है।

<u>रिट याचिका (आपराधिक) संख्या - 203/2015</u>

26. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर यह रिट याचिका उसी आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित निरूद्ध आदेश संख्या एफ.673/13/2015-Cus.VIII 34 दिनांक

27.04.2015 को चुनौती देती है, जिसका निस्तारण विस्तृत रूप से आपराधिक अपील संख्या 2281 /2014 में किया जा चुका है। यही कारण है कि याचिका को उक्त अपील के साथ टैग किया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने रिट याचिका की विचारणीयता पर बहस करने के अलावा, उपरोक्त अपील में वरिष्ठ वकील श्री चौधरी द्वारा दिए गए तर्कों को अपनाया। ऊपर दिए गए कारणों से यह रिट याचिका भी खारिज की जाती है।

दिव्या पांडे

अपील और रिट याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।